

कांग्रेस दर्पण

पटना, 15 जून, शनिवार, 2024

बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवादल सदाकत आश्रम पटना-10

'नीट-स्नातक' : 'व्यापम 2.0'

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

नई दिल्ली। कांग्रेस ने चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश से जुड़ी परीक्षा 'नीट-स्नातक' में कथित धांधली को लेकर शुक्रवार को इसे 'व्यापम 2.0' करार दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस पर मूकदर्शक बने नहीं रह सकते। मुख्य विपक्षी दल ने कहा कि इस मामले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में फोरेंसिक जांच होनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक बयान में आरोप लगाया कि मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री व एनटीए ने नीट घोटाले की लीपापोती चालू कर दी है।

पेपर लीक नहीं हुआ तो गिरफ्तारियां क्यों हुईं?

उन्होंने सवाल किया, "अगर नीट में पेपर लीक नहीं हुआ तो बिहार में 13 आरोपियों को पेपर लीक के चलते गिरफ्तार क्यों किया गया? क्या रैकेट में शामिल शिक्षा माफिया व संगठित गिरोह को पेपर के बदले 30-50 लाख रुपये तक के भुगतान का पटना पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पर्दाफाश नहीं किया? गुजरात के गोधरा में नीट-स्नातक में धोखाधड़ी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ नहीं हुआ है?" उन्होंने यह सवाल भी किया, "अगर मोदी सरकार के मुताबिक नीट में कोई पेपर लीक नहीं हुआ तो ये गिरफ्तारियां क्यों हुईं? इससे क्या निष्कर्ष निकला? क्या मोदी सरकार देश की जनता की आंखों में पहले धूल झाँक रही थी या अब?"

सरकार ने 24 लाख युवाओं के अरमानों का गला घोट

खरगे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने 24 लाख युवाओं के अरमानों का गला घोट है। उन्होंने दावा किया, "इन एक लाख सीटों (एमबीबीएस की) में से करीब 55,000 सरकारी कॉलेजों की सीट हैं जहां एससी, एसटी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। मोदी सरकार ने एनटीए का दुरुपयोग कर स्कोर और रैंक की जोरदार धांधली की है जिससे

कांग्रेस ने चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश से जुड़ी परीक्षा 'नीट-स्नातक' में कथित धांधली को लेकर 'व्यापम 2.0' करार दिया

आरक्षित सीटों का कटऑफ भी बढ़ गया है।"

'नीट घोटाला' 'व्यापम 2.0' है- पवन खेड़ा

कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि 'नीट घोटाला' 'व्यापम 2.0' है जिस पर मोदी सरकार लीपापोती करना चाहती है। उन्होंने कहा, "मोदी सरकार को नीट घोटाले में उच्चतम न्यायालय न्यायालय की निगरानी में स्वतंत्र फोरेंसिक जांच का आदेश देना चाहिए।" खेड़ा ने कहा कि कुछ भी गड़बड़ नहीं होने संबंधी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान 'शर्मनाक' और छात्रों



के घावों नमक छिड़कने की तरह है। उन्होंने कहा, "क्या यह सच नहीं है कि इस साल 67 टॉपर थे जिन्हें 720 पूर्णोंक मिले? 2023 में यह संख्या सिर्फ दो थी। 2022 में कोई भी अभ्यर्थी पूरे अंक हासिल नहीं कर सका। 2021 में सिर्फ तीन उम्मीदवार ही यह स्कोर हासिल कर सके।"

प्रधानमंत्री हमेशा की तरह चुप क्यों हैं- कांग्रेस

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी हमेशा मूकदर्शक नहीं रह सकते। जब 24 लाख युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है, तो वे चुप क्यों हैं?"

खेड़ा का कहना था, "अगर मोदी सरकार का दावा है कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी है, तो उसे पिछले साल और इस साल 580 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का पूरा परिणाम एनटीए द्वारा सार्वजनिक किया जाना चाहिए। 580 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के केंद्रों को भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि पता चल सके कि कितने छात्र अपने स्थान से दूर नीट परीक्षा देने आए थे।" उन्होंने कहा, "लाखों युवा छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए केवल उच्चतम न्यायालय की निगरानी में फोरेंसिक जांच ही एक समाधान है। मोदी सरकार को खुद को देश के प्रति जवाबदेह बनाना चाहिए।"



राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ सदस्य इंद्रेश कुमार की हालिया टिप्पणी पर कांग्रेस ने दी तीखी प्रतिक्रिया

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के वरिष्ठ सदस्य इंद्रेश कुमार की हालिया टिप्पणी पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि आज की तारीख में संघ को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ₹ आरएसएस को कौन गंभीरता से लेता है? पीएम मोदी भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते, तो हम क्यों लें? अगर वह (इंद्रेश कुमार) समय पर बोलते, तो हर कोई उन्हें गंभीरता से लेता लेकिन उस समय वे (आरएसएस) चुप रहे और सत्ता का आनंद लेते रहे। खेड़ा ने यह भी कहा कि बीते 10 वर्षों में मोहन भागवत ने भी कई अहम मुद्दों पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन वह अब बोल रहे हैं।

बता दें कि मोहन भागवत के बयान के बाद संघ नेता इंद्रेश कुमार ने सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी इंडिया अलायंस की आलोचना की थी और सत्तारूढ़ बीजेपी को 'अहंकारी' और विपक्षी इंडिया ब्लॉक को 'राम विरोधी' करार दिया था। इंद्रेश कुमार ने कहा, ₹ राम सबके साथ न्याय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए। जिन्होंने राम की भक्ति की, लेकिन उनमें धीरे-धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया लेकिन जो उसको पूर्ण हक मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए थी, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी।

इंद्रेश कुमार ने आगे कहा, ₹ जिन्होंने राम का विरोध किया, उन्हें बिल्कुल भी शक्ति नहीं दी। राम का विरोध करने वालों में से किसी को भी सत्ता नहीं मिली, यहां तक कि सभी को मिलाकर दूसरे नंबर पर खड़ा कर दिया गया। ₹ जयपुर में उन्होंने कहा कि भगवान का न्याय बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। उन्होंने स्पष्ट रूप से सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन



दोनों पर निशाना साधा। हालांकि, उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया।

इंद्रेश कुमार ने कहा, ₹ लोकतंत्र में रामराज्य का 'विधान' देखिए, जिन्होंने राम की भक्ति की, लेकिन धीरे-धीरे अहंकारी हो गए, वह पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन जो वोट और सत्ता (अकेले पूर्ण बहुमत) मिलनी चाहिए थी, उसे भगवान ने अहंकार के

कारण रोक दिया।' उन्होंने कहा कि भक्ति करने वाली पार्टी अहंकारी हो गई, उसे 241 पर ही भगवान ने रोक दिया, लेकिन उसे सबसे बड़ी पार्टी बना दिया और जिनकी राम में आस्था नहीं थी, उन सबको मिलकर भगवान ने 234 पर रोक दिया।

कुमार जयपुर के पास कानोता में 'रामरथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह' को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा, "जिसने लोगों पर अत्याचार किया, राम जी ने उससे कहा कि पांच साल आराम करो, अगली बार देखेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है।" उन्होंने कहा कि राम ने सबको न्याय दिया, देते हैं और देते रहेंगे, राम हमेशा न्यायप्रिय थे और रहेंगे।

प्रियंका गांधी ने जंगल की आग में जलने से चार वन कर्मियों की मौत पर जताया दुख, की अपील

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

नई दिल्ली। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा ने अल्मोड़ा में जंगल की आग में जलने से हुई चार वन कर्मियों की मौत और चार कर्मियों के घायल होने के मामले में अपने ट्विटर अकाउंट एक्स के जरिए घटना पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड में जंगल की आग बुझाने गए चार कर्मचारियों की मृत्यु और कई अन्य के घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद है। सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। पीड़ित परिवारों को मुआवजा और हर संभव स्तर पर सहायता का आग्रह मैं राज्य सरकार से करती हूँ। उन्होंने लंबे समय से पर्वतीय क्षेत्रों में

सुलग रहे जंगलों को लेकर भी चिंता जताई है। लिखा है कि पिछले कई महीने से उत्तराखंड के जंगल लगातार जल रहे हैं। सैकड़ों हेक्टेयर जंगल तबाह हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में भी जंगलों में जगह-जगह आग लगने की सूचनाएं हैं। एक स्टडी के मुताबिक हिमालय क्षेत्र के जंगलों में आग लगने की घटनाओं में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक असर हमारे हिमालय और पर्वतीय पर्यावरण पर हुआ है। मेरी केंद्र और राज्य सरकारों से अपील है कि आग लगने की घटनाओं के रोकने के उपाय हों और हिमालय को बचाने के लिए सबके सहयोग से व्यापक स्तर पर कारगर प्रयास किए जाएं।





कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के गेहूं की खरीद पर खड़े किए सवाल

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के गेहूं की खरीद पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि गेहूं के सरकारी भंडारों में हर वक्त तीन महीने का स्टॉक रहना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश के पास इस बार खरीद सत्र शुरू होने से पहले सिर्फ 75 लाख टन गेहूं था। पटवारी ने कहा कि अपने यहां अभी तक पिछली बार से करीब 22.67 लाख टन कम खरीद हुई है और अब सब जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ।

एक साल में 8 और 15 दिन में 7 प्रतिशत बढ़े गेहूं के दाम

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने कहा है कि गेहूं एक साल में 8 प्रतिशत महंगा हुआ है। पिछले 15 दिन में ही कीमतें 7 प्रतिशत बढ़ चुकी हैं, जो अगले 15 दिन में 7 प्रतिशत और बढ़ सकती हैं। दरअसल, गेहूं के सरकारी भंडारों में हर वक्त तीन महीने का स्टॉक (138 लाख टन) होना चाहिए। मगर इस बार खरीद सत्र शुरू होने से पहले यह सिर्फ 75 लाख टन था। 2023 में यह 84 लाख टन, 2022 में 180 लाख टन और 2021 में 280 लाख टन स्टॉक था। यानी अभी यह 16 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पर आ गया है।

पटवारी ने कहा कि सीएम मोहन यादव जी



कृषि विशेषज्ञों का मानना है गेहूं के फसल चक्र के दौरान कोहरे, हवा के कारण इसकी प्रति एकड़ उत्पादकता 5 क्विंटल तक कम हो गई है। दूसरा सबसे बड़ा दोष मध्य प्रदेश का है। अपने यहां अभी तक पिछली बार से करीब 22.67 लाख टन कम खरीद हुई है। अब तो देश भी जानना चाहता है कि ऐसा क्यों हुआ? कई बार, लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार जीतने वाला मध्य प्रदेश गेहूं की खरीद में क्यों पिछड़ गया? क्या किसानों को अब भाजपा की

खरीद व्यवस्था पर विश्वास नहीं रहा? मैं जानता हूं कि आप इसका जवाब नहीं देंगे।

पटवारी ने बोले कि प्रदेश की जनता और मेहनतकश किसान जानता है कि सच क्या है? घोषित समर्थन मूल्य से सरकार का मुकर जाना इसकी सबसे बड़ी वजह है। बीते विधानसभा चुनाव में 2700 रुपये प्रति क्विंटल के वादे को मोदी की गारंटी बताने के बावजूद किसानों को धोखा दिया गया। इसीलिए सरकार के बयान से ज्यादा किसानों

ने बाजार पर भरोसा कर लिया। मुनाफे की नीति पर चलने वाला बाजार अब अपनी शर्तों पर गेहूं और आटे की कीमत तय करेगा और इसका सबसे बड़ा खामियाजा देश की गरीब जनता को भुगतना पड़ेगा। गेहूं के जरिए आए महंगाई के इस नए संकट के लिए सबसे ज्यादा आपकी सरकार और उसके वादाखिलाफी जिम्मेदार है। अभी भी समय है। किसानों से माफी मांगें और उन्हें बकाया भुगतान कर दें।

आज सिरसा से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद डबवाली के चौटाला रोड पर स्थित ओम होटल में आयोजित कार्यक्रम में हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं का धन्यवाद किया। भारी संख्या में उपस्थित होकर आपने जो समर्थन और प्रेम दिखाया, उस प्रेम का आभार व्यक्त करना शब्द की सीमाओं से परे है, आपकी मेहनत और समर्पण ने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया है। यह समय रुकने का नहीं है। हमें इसी ऊर्जा के साथ विधानसभा चुनावों के लिए कमर कसनी है और हरियाणा में कांग्रेस का परचम लहराना है।





कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर कसा तंज

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद देश के लिए फिर से काम करना शुरू कर दिया है। इस बीच नेताओं की एक दूसरे पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। अब कांग्रेस ने पीएम मोदी पर महंगाई को लेकर निशाना साधा है। बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखते हुए कहा, मोदी है तो महंगाई है! चार महीनों से खानों की चीजों के दाम 8.5% से अधिक हो गए हैं। दालों में 10% से अधिक महंगाई बढ़ी है! मई में कीमतें 17.14% बढ़ी हैं।

विपक्षी दल का यह बयान हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों के एक दिन बाद आया है जिसमें कहा गया है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में मामूली गिरावट के कारण मई में खुदरा मुद्रास्फीति (पीइः क्लरिड ३ इन्ड्ल) में गिरावट जारी रही और यह एक साल के निचले स्तर 4.75 प्रतिशत पर पहुंच गई।

जयराम रमेश के मुताबिक, घोषणापत्र में पीडीएस में दालों को शामिल करने, गरीबों के लिए प्रोटीन का सेवन बढ़ाने और उन्हें महंगाई से बचाने की भी वकालत की गई थी। जयराम रमेश ने कहा, दालों की महंगाई दर पिछले एक साल में लगातार दोहरे अंक में झू 10% से ज्यादा है, मई में कीमतें 17.14% बढ़ी हैं। उन्होंने आगे कहा प्रधानमंत्री के पास इस संकट का कोई समाधान नहीं है।' नेशनल स्टेटिस्टिक्स डाटा की तरफ से आई जानकारी के मुताबिक, महंगाई मई में 8.69 प्रतिशत थी। इसके बाद ये अप्रैल में 8.70 प्रतिशत से थोड़ी कम हो गई। जनवरी 2024 से महंगाई के आंकड़ों में काफी बदलाव देखा गया। फरवरी में 5.1 प्रतिशत



से लेकर अप्रैल 2024 में 4.8 प्रतिशत तक थी।

एनएसओ के आंकड़ों से पता चला है कि शहरी क्षेत्रों में 4.15 प्रतिशत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में

महंगाई 5.28 प्रतिशत अधिक है। मई के दौरान सब्जियों की महंगाई पिछले महीने की तुलना में अधिक थी, जबकि फलों के मामले में यह कम थी। सरकार ने

रिजर्व बैंक को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा है कि सीपीआई महंगाई दोनों तरफ 2 प्रतिशत के मार्जिन के साथ 4 प्रतिशत पर बनी रहे।

अमेठी की पूर्व एक्सिडेंटल सांसद जी के संरक्षण में उनके करीबियों ने भ्रष्टाचार कर खूब पैसे बनाए। अब उनकी विदाई के बाद उनके भ्रष्टाचार की परतें उखड़नी शुरू हो चुकी हैं। जगदीशपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत पिछूती निवासी अमित कुमार सिंह ने ग्राम प्रधान एकता मिश्रा (इनके पति रमेश मिश्रा स्मृति ईरानी के नवरत्नों में से एक है) द्वारा विभिन्न विकास कार्यों में 21 लाख से अधिक के अनियमित भुगतान की शिकायत जिलाधिकार से की थी। प्रकरण की जांच रिपोर्ट में शिकायत सही मिली है। स्मृति जी अमेठी वासियों को 13 रुपए की चीनी भले ही नहीं दिलवा पाई पर अपने नवरत्नों के भ्रष्टाचार को फलने-फूलने में कोई कमी नहीं रखी।

स्मृति ईरानी के नवरत्नों में से एक प्रधानपति ने किया 21 लाख का घोटाला





नीट परीक्षा में 'धांधली' का मुद्दा संसद सत्र के दौरान उठाया जाएगा: कांग्रेस

संवाददाता | कांग्रेस दर्पण

नई दिल्ली। कांग्रेस ने चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित 'राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा - स्नातक' (नीट-यूजी), 2024 में कथित धांधली की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग फिर उठाई और कहा कि 24 जून से आरंभ हो रहे संसद के सत्र के दौरान इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया जाएगा।

पार्टी नेता गौरव गोगोई ने कहा कि कांग्रेस इस मामले में सीबीआई जांच चाहती है, लेकिन अगर सरकार इसके लिए तैयार नहीं है तो फिर उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच होनी चाहिए।

मुख्य विपक्षी पार्टी इस मामले में लगातार यह मांग कर रही है।

केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि नीट (स्नातक) के 1,563 अभ्यर्थियों को कृपांक (ग्रेस मार्क) देने के फैसले को निरस्त कर दिया गया है और उन्हें 23 जून को पुनः परीक्षा देने का विकल्प मिलेगा।

केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के वकीलों ने न्यायमूर्ति विन्मनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ को बताया कि जिन विद्यार्थियों को कृपांक दिए गए थे, उन्हें पुनः परीक्षा का विकल्प दिया जाएगा।

उधर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने नीट में प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों को खारिज करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि इसका कोई प्रमाण नहीं है।

कांग्रेस सांसद गोगोई ने संवाददाताओं से कहा, "नीट परीक्षा में हुई धांधली के आरोपों पर सरकार का जो रवैया रहा है, उस पर उन्हें आत्ममंथन करने की जरूरत है। उच्चतम न्यायालय की सुनवाई में सरकार ने जताया है कि 1563 छात्रों का स्कोरकार्ड हड़ किया जाएगा और उन्हें 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प मिलेगा। वे बच्चे जो दोबारा परीक्षा नहीं देना



चाहते, उनके कृपांक हटाने के बाद जो अंक रहेंगे, वही फाइनल अंक माने जाएंगे। जो छात्र 23 जून को दोबारा परीक्षा देंगे, उनका 30 जून को परिणाम आएगा और फिर 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होगी।"

उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान इस मामले पर चर्चा से भाग रहे हैं।

गोगोई ने कहा, "जिस एनटीए के नेतृत्व में यह पूरा घोटाला हुआ, आप उसी एजेंसी से मामले में जांच करने की बात कह रहे हैं। ऐसे में निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जा सकती है?"

उन्होंने कहा, "परीक्षा केंद्र और कोचिंग सेंटर का एक गठजोड़ बन चुका है, जिसने आज हमारे मध्यम-गरीब वर्ग को हिला कर रख दिया है। 'पैसे दो-पेपर लो' जैसी सांठगांठ की जांच एनटीए कैसे कर पायेगा? इसमें एनटीए का कोई न कोई अधिकारी शामिल

है। ऐसे में एनटीए निष्पक्ष जांच कैसे करेगा?"

कांग्रेस सांसद ने कहा, "कांग्रेस इस मामले में सीबीआई जांच चाहती है। यदि सरकार सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं है तो हम उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग करते हैं।"

गोगोई ने दावा किया, "हमने अलग-अलग रिकॉर्डिंग सुनी है कि कैसे लाखों रुपये मांगे जा रहे हैं। एक ही सेंटर में बच्चों को एक जैसे नंबर मिल रहे हैं। इस मामले पर सरकार का रवैया कमजोर रहा है और वह इस मुद्दे से भाग रही है। लेकिन देश के मुद्दों को उठाना विपक्ष का कर्तव्य है और हम सदन के अंदर अपने 24 लाख छात्रों की आवाज जोर-शोर से उठाएंगे।"

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा

(नीट) में एनटीए की भूमिका को संदेहास्पद बताते हुए कहा है कि अगर सरकार की अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने की मंशा है तो नीट परीक्षा को लेकर जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए।

गहलोत ने गुरुवार को यहां सोशल मीडिया पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर आ रही सूचनाओं से यह स्पष्ट है कि यह पूरी परीक्षा संदेह के घेरे में है। परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए की भूमिका ही संदेहास्पद है। यदि सरकार की अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने की मंशा है तो नीट परीक्षा को लेकर जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अगर मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में ही ऐसी अनियमितताएं हो जाएंगी तो यह देश में मेडिकल सेवाओं के भविष्य पर सवालिया निशान लगा देगा।

प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सांसद श्री Deepak B जी, नेता प्रतिपक्ष श्री Dr. Charan Das Mahant जी व पूर्व मुख्यमंत्री श्री Bhupesh Baghel जी ने आज कांग्रेस भवन, बलौदाबाजार में विशेष पत्रकार वार्ता को संबोधित कर कहा कि बलौदाबाजार की घटना से हमारा प्रदेश कलंकित हुआ है। मौजूदा सरकार पूरी तरह से असक्षम है। घटना के बाद शासन-प्रशासन निर्दोष लोगों के साथ बर्बरता से पेश आ रही है। भाजपा सरकार का अब प्रशासन से भी भरोसा उठ गया है, इसलिए उन्हें स्वयं की जाँच समिति बनानी पड़ी। अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता खामोश नहीं बैठेगा।





सच्चाई

ये हैं राजस्थान की
ओसिया विधानसभा की
पूर्व विधायक सुश्री
दिव्या मदेरणा जी



झूठ

BJP IT सेल द्वारा इन्हें
कंगना को थप्पड़ मारने वाली
CISF की महिला कांस्टेबल
कुलविंदर कौर बताया जा रहा है।

"माहब्बत को दुकान" के ठेकेदारों के साथ कुलावदर कार
जिसने कंगना रनौत पर हमला किया..!

यह चित्र देखकर आगे पीछे की सारी कहानी समझ
चुके होंगे आप सभी..! 😡😡😡





युवाओं के सपनों को इस परीक्षा प्रणाली की भेंट चढ़ाना बंद होना चाहिए?

संवाददाता | कांग्रेस दर्पण

भाजपा की नई सरकार ने शपथ लेते ही युवा सपनों पर फिर से प्रहार शुरू कर दिया। ठण्डा परीक्षा परिणाम में गड़बड़ियों पर शिक्षा मंत्री का अहंकार भरा जवाब 24 लाख छात्रों एवं उनके अभिभावकों की चीख-पुकार की पूरी तरह से अनदेखी करता है। क्या शिक्षा मंत्री जी को सार्वजनिक रूप से मौजूद तथ्य नहीं दिखते? क्या बिहार और गुजरात में जो पुलिस कार्रवाइयां हुईं और रैकेट पकड़े गए, सरकार उन्हें भी झूठा मानती है?

क्या 67 टॉपर को पूरे मार्क्स मिलना भी झूठ है?

सवाल यह है कि लाखों युवाओं और उनके माता-पिता की अनदेखी कर सरकार सिस्टम में किसको बचाना चाहती है?

क्या युवाओं के सपनों को इस भ्रष्ट परीक्षा प्रणाली की भेंट चढ़ाना बंद नहीं होना चाहिए?

क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि छात्रों व अभिभावकों की बात की अनदेखी करने की बजाय, शिकायतों पर गंभीरता से गौर करे व एक्शन ले?

भाजपा सरकार को अपना अहंकार त्यागकर युवाओं के भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और परीक्षाओं में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उपाय करने चाहिए।

श्रीमती प्रियंका गांधी वाड़ा



प्रदेश के बलौदाबाजार में हुई हिंसक घटना के मामले में आज प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सांसद श्री Deepak Baij जी, नेता प्रतिपक्ष श्री Dr. Charan Das Mahant जी व पूर्व मुख्यमंत्री श्री Bhupesh Baghel जी के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विधायक गण व पदाधिकारियों का दल घटना स्थल का निरक्षण करने राजीव भवन, रायपुर से बलौदाबाजार के लिए रवाना हुआ। इस दौरान वे समाज के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे।

